

मेसर्स भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य

बनाम

भारत का संघ अन्य

(सिविल अपील संख्या 7823/2014)

24 मार्च, 2017

[जे. चेलामेश्वर और अभय मनोहर सप्रे,जे.जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-धारा 3ए-को शामिल करने का धारा 3 ए-चर्चा की गई।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944- आर.आर 96 जेड पी (3) और 96 जेड ओ (3)-क्या एक निर्धारिती जो आर 96 जेड पी (3) के संदर्भ में शुल्क का भुगतान करने के लिए एक बार चुनता है, उसे वास्तविक उत्पादन की परवाह किए बिना आने वाले सभी समय के लिए उक्त नियम के अनुसार गणना किए गए शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है-विभाग ने वीनस कास्टिंग्स और सुप्रीम स्टील मामले पर भरोसा किया जो सर्वोच्च अदालत द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि निर्धारिती जो आर के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए एक बार विकल्प चुनता है। 96 जेड. पी. (3) अपनी पसंद से आगे नहीं बढ़ सकते-हालाँकि, इन दोनों मामलों में सर्वोच्च अदालत आर. 96 जेड ओ (3)-वीनस कास्टिंग्स में, 96ZP का संदर्भ दिया गया था और यह देखा गया था कि आर. 96 जेड ओ और r.96 जेड पी सिल्लियों और बिलेट और गर्म पुनः रोल किए गए उत्पादों के निर्माता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करता है और योजना में परिकल्पना की गई है कि ये प्रावधान समान थे- आयोजित:इन नियमों के बीच व्यापक समानताएं हैं लेकिन वे समान नहीं हैं-आर

96 जेड ओ (3) और आर 96 जेड पी (3) के बीच एकमात्र समानता यह है कि दोनों नियम प्रक्रिया यू/एस के लाभ को समाप्त करना चाहते हैं।<sup>3</sup> अधिनियम के ए (4) उन निर्धारिती के मामलों में जो उप-नियमों (3) के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने का विकल्प चुनते हैं, जो यू/आरआर के तहत प्रदान किए गए शुल्क और संग्रह के सामान्य नियमों के अपवाद हैं। 96 जेड. ओ. और 96 जेड. पी.-इसलिए, विभाग की इस दलील को प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल है कि यह मुद्दा वीनस कास्टिंग्स और सुप्रीम स्टील्स में दिए गए इस अदालत के फैसलों के दायरे में आता है-इन दोनों फैसलों के लिए आगे की जांच की आवश्यकता है-इसके अलावा, ये फैसले आर 96 जेड. पी. (3) के अधिकारों से संबंधित नहीं थे-हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुप्रीम स्टील्स तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है, यह उचित माना जाता है कि कानून के प्रश्न का निपटारा एक उचित शक्ति की पीठ द्वारा किया जाए-मामला बड़ी पीठ को संदर्भित किया जाता है-हॉट री-रोलिंग स्टील मिल्स वार्षिक क्षमता निर्धारण नियम, 1997-3-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-धारा. 3. ए.- बड़ी पीठ को संदर्भ।

विधियों की व्याख्या:

कानूनी कल्पना और अनुमान-के बीच अंतर-आयोजित:एक कल्पना कुछ ऐसा मानती है जिसे गलत माना जाता है, जबकि अनुमान कुछ ऐसा मानती है जो संभवतः सच हो सकता है।

कानूनी कल्पना-केवल संप्रभु विधायी निकाय ही कानूनी कल्पना का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन एक अधीनस्थ कानून बनाने वाला निकाय नहीं।

न्यायालय द्वारा मामले को बड़ी पीठ पर संदर्भित करते हुए, अभिनिर्धारित किया

गया :-

1. संसद ने समय-समय पर इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कुछ उत्पादक /उत्पादक अपने द्वारा किए गए माल के वास्तविक उत्पादन/निर्माण की मात्रा की जानकारी को दबा कर शुल्क से बच रहे हैं।इसलिए, धारा 3 ए पेश की गई जिसने अधिसूचित वस्तुओं पर शुल्क लगाने, मूल्यांकन करने और उत्पाद शुल्क के संग्रह के एक अलग तरीके को अधिकृत किया।धारा 3 ए की योजना के तहत, उत्पादित/निर्मित अधिसूचित वस्तुओं की वास्तविक मात्रा की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता को यह घोषणा करके समाप्त कर दिया जाता है कि कारखाने के एसीपी को उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने के उद्देश्य से कारखाने का वार्षिक उत्पादन माना जाता है।[पैरा 24] [1010-बी-सी]

2. हॉट री-रोलिंग स्टील मिल्स वार्षिक क्षमता निर्धारण नियम, 1997 ने आइए प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा एसीपी का निर्धारण किया जाना है, नियम 3 ने एसीपी के निर्धारण के लिए आइएमें उल्लिखित विभिन्न कारकों के आधार पर एक सूत्र निर्धारित किया। अपीलकर्ता की शिकायत नियम 5 के खिलाफ है जो आदेश देता है कि नियम 3 के अनुसार निर्धारित एसीपी को नियम 5 के तहत उल्लिखित परिस्थितियों में खारिज कर दिया जाए।नियम 5 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि पूर्ववर्ती चार नियमों के अनुसार निर्धारित ए. सी. पी. वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष निर्धारिती के वास्तविक उत्पादन से कम है, तो ए. सी. पी. का निर्धारण करने वाले प्राधिकरण को नियम 1 से 4 में निहित प्रक्रिया को नियोजित करके प्राप्त ए. सी. पी. के आंकड़े को परित्याग करना होगा और उस निर्धारिती के ए. सी. पी. के रूप में वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा प्राप्त वास्तविक उत्पादन को अपनाना होगा।धारा 3 ए (2) और नियम 5 दोनों में आने वाले शब्द "माने जाएंगे" एक कल्पना की रचना करते

प्रतीत होते हैं।लेकिन एक सच्चे और उचित निर्माण पर वे एक कानूनी कल्पना नहीं बनाते हैं।धारा 3 ए (2) केवल बुराई के एक नियम का प्रतीक है जो विभाग को कुछ तथ्यों का अनुमान लगाने का आदेश देता है।इस तरह के अनुमान कानून के लिए अज्ञात नहीं हैं।भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 की धारा 114 साक्ष्य का एक नियम अधिनियमित करती है जिसमें एक अदालत को किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो अदालत को लगता है कि प्राकृतिक घटनाओं आदि के सामान्य पाठ्यक्रम के संबंध में हुआ था। नियम 5 के तहत बनाई गई धारणा साक्ष्य की धारा 114 के चित्रण (डी) में निहित धारणा के समान है जो कानूनी कल्पना और धारणा के बीच कानून में एक स्पष्ट अंतर है।एक कल्पना कुछ ऐसा मानती है जिसे गलत माना जाता है; एक धारणा (चाहे निर्णायक हो या खंडन योग्य) कुछ ऐसा मानती है जो संभवतः सच हो सकता है।इस भेद को प्रबलित माना जाता है, जैसा कि खंडन योग्य अनुमान के मामले में किया गया था, क्योंकि इस तरह की धारणा एक ऐसे तथ्य को मानती है जो स्वाभाविक रूप से सच है।"अनुमान कानूनी कल्पनाओं से निकटता से संबंधित हैं. लेकिन वे अलग तरह से काम करते हैं।"कल्पनाएँ हमेशा वास्तविकता के साथ संघर्ष करती हैं, जबकि धारणाएँ सच साबित हो सकती हैं।कानूनी कल्पनाएँ विधायिका के जनादेश द्वारा एक कृत्रिम स्थिति पैदा करती हैं।वे अदालतों सहित सभी संबंधित लोगों को तथ्यों की वास्तविक स्थिति के विपरीत तथ्यों की एक कृत्रिम स्थिति के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं।जब कानून द्वारा एक काल्पनिक कथा बनाई जाती है, तो यह किसी के लिए भी यह दलील देने या तर्क देने के लिए खुला नहीं होता है कि कानून द्वारा बनाए गए तथ्यों की कृत्रिम स्थिति सच नहीं है, एकमात्र संभव पाठ्यक्रम को छोड़कर यदि उपलब्ध हो तो कल्पना की संवैधानिकता पर प्रश्न उठाना है।यह एक स्थापित कानून है

कि केवल सामान्य विधायी निकाय ही कानूनी कल्पनाएँ बना सकते हैं, लेकिन एक अधीनस्थ कानून बनाने वाला निकाय नहीं। [पैरा 25,30,31 और 32] [1016-सी-डी; 1012-8-डी; 1013-ए-डी; 1014-ए-बी]

3. साक्ष्य के नियम कानून के वे सिद्धांत हैं जो अदालतों या अन्य निकायों को आदेश देते हैं जिनका कर्तव्य कुछ तथ्यों के अस्तित्व या अन्यथा का निर्धारण करना है। एंग्लो सैक्सन कानूनी प्रणाली यह मानती है कि तथ्यों को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है, कुछ तथ्यों को मानते हुए, यदि वे कानून द्वारा आदेशित हैं, तो हमारी कानूनी प्रणाली द्वारा हमेशा उन निकायों के लिए स्वीकृत प्रक्रियाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है जिन पर साक्ष्य एकत्र करने का कर्तव्य है। इसलिए, कानून बनाने वाले निकाय जहां भी उचित समझते हैं, वहां अनुमानों को शामिल करने के प्रावधान करते हैं। लेकिन इस तरह की प्रथाओं में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त योग्यता और सीमाएँ हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में अनुमानों के कानून के कुछ बुनियादी सिद्धांतों और उन पर सीमाओं का समावेश है। तकनीकी रूप से, साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य एकत्र करने की जिम्मेदारी वाले प्रत्येक निकाय पर लागू हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन प्रावधानों में अंतर्निहित सिद्धांत मूल्यवान मार्गदर्शक हैं। वे मानव आचरण, घटनाओं के प्राकृतिक पाठ्यक्रम और तर्क के अवलोकन से प्राप्त न्यायशास्त्र के ठोस सिद्धांतों पर आधारित हैं। [पैरा 34} [1014-ई; 1015-ए-बी]

4. अधिनियम की योजना के तहत, एक उद्योग (निर्माता) के उत्पादन की वास्तविक मात्रा निर्माता के कर दायित्व को निर्धारित करने के लिए आवश्यक कारकों में से एक है। धारा 3 ए (2) और नियम 5 दोनों ही अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखाने के उत्पादन की मात्रा के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित हैं।

अधिनियम की धारा 3 ए सरकार को निर्माताओं के एसीपी निर्धारित करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। यह आगे घोषणा करता है कि इस प्रकार निर्धारित ए. सी. पी. को "ऐसे कारखाने द्वारा ऐसी वस्तुओं का वार्षिक उत्पादन माना जाएगा।" दूसरे शब्दों में उप-धारा (2) आदेश देती है कि एक कारखाना जिसका एसीपी उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, यह माना जाना चाहिए कि वह प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के लिए एसीपी के बराबर माल का समान मात्रा में उत्पादन करता है। परिभाषा के अनुसार "कल्पना हमेशा वास्तविकता के साथ संघर्ष करती है जबकि अनुमान सच साबित हो सकता है।" इसलिए, यह इस प्रकार है कि साक्ष्य द्वारा किसी कल्पना का खंडन किए जाने की कोई संभावना नहीं है। एक निर्माता के वार्षिक उत्पादन के संबंध में धारा 3 ए (2) से बहने वाले विश्वास का खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करके किया जा सकता है। धारा 3 ए (4) में इस तरह के खंडन का प्रावधान है। इसलिए, धारा 3 ए (2) केवल साक्ष्य के नियम (अनुमान) का प्रतीक है, लेकिन यह एक काल्पनिक कल्पना नहीं है। ड्राफ्ट्समैन द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा इस निष्कर्ष पर गुमराह कर सकती है कि एक काल्पनिक कथा बनाई गई है। लेकिन पूरी धारा 3 ए के सही और उचित निर्माण पर एकमात्र संभव निष्कर्ष यह है कि धारा 3 ए (2 जेड) केवल एक अनुमान (साक्ष्य का नियम) का प्रतीक है। [पारस 36-38} [1015-डी, एच; 1016-ए-डी],

5. 1997 के नियमों की योजना के तहत, पहले चार नियमों में उस वर्ग के निर्माताओं के ए. सी. पी. का निर्धारण करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, जिसमें अपीलार्थी निर्माता द्वारा नियोजित मशीनरी से संबंधित तकनीकी डेटा के संबंध में एक उचित अनुमान लगाते हैं। विधायक इस तथ्य से अवगत थे कि एक कारखाने में निर्मित की जा सकने वाली वस्तुओं की वास्तविक मात्रा केवल (कारखाने के एसीपी) पर निर्भर

नहीं करती है। यह कई अन्य परिवर्तनशील कारकों पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक निर्माता द्वारा नियोजित मशीनरी के पास वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा (अधिकतम उत्पादन) का उत्पादन करने की तकनीकी क्षमता है, एक निश्चित समय अंतराल में निर्माता हमेशा अधिकतम उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि कारखाने या वित्त या कच्चे माल आदि को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की अनुपलब्धता है। 1997 के नियम के पहले चार नियम साक्ष्य की एक योजना बनाते हैं जिसके द्वारा उत्पादन की एक निश्चित मात्रा की संभावना का अनुमान (निर्माताओं की मशीनरी के तकनीकी विनिर्देश के आधार पर) लगाया जाता है। हालांकि, कानून निर्माता ने कल्पना की कि कुछ मामलों में ऐसी प्रक्रिया से यह धारणा बन सकती है कि एक निर्माता का एसीपी वास्तविक उत्पादन से कम है जो पहले के समय में एक ही मशीनरी को नियोजित करके प्राप्त किया गया था-एक निष्कर्ष जो स्थापित तथ्यात्मक डेटा के साथ असंगत है। इसलिए, नियम 5 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में कारखाने के एसीपी को 1997 के नियम लागू होने से पहले वित्तीय वर्ष में प्राप्त वास्तविक उत्पादन के बराबर माना जाना चाहिए। नियम 5 नियम 3 में निहित सूत्र को लागू करके एसीपी तक पहुंचने में त्रुटि की संभावना को पहचानता है। क्योंकि सूत्र स्वयं कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए, नियम 5 में यह प्रावधान है कि नियम 3 में निहित प्रक्रिया के अनुसार किए गए ए. सी. पी. का निर्धारण कुछ मामलों में उसमें दर्शाई गई परिस्थितियों में सुधार के लिए उत्तरदायी है। लेकिन धारा 3 ए (4) का लाभ यानी वार्षिक उत्पादन के संबंध में धारणा का खंडन करने का अधिकार नियम 96 जेड, पी (3) के तहत आने वाले निर्माताओं के उप-वर्ग को नहीं दिया जाता है।

जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 जेडपी की योजना के तहत आने

वाले एक बड़े वर्ग का भी हिस्सा हैं।लेकिन नियम 96 जेडपी के उप-नियम (3) की घोषणा के लिए, एक निर्धारिती जो 1997 के नियमों के नियम 3 के अनुसार निर्धारित किया गया है, अधिनियम की धारा 3 ए की उप-धारा (4) के तहत अपने वास्तविक उत्पादन और उस में कर देयता के निर्धारण की मांग करने का हकदार होगा।[पारस 39-41] [1016-ई-एच; 1017-ए-डी]

6. ए.सी.पी. का निर्धारण एक बार का मामला है।नियम 3 में बताए गए कारकों से यह प्रतीत होता है कि ए.सी.पी. तब तक अपरिवर्तित रहेगा जब तक कि नियोजित विषय-वस्तु मशीनरी में कोई बदलाव नहीं होता है और विषय-वस्तु मशीनरी के 'उपयोग किए गए घंटों की संख्या' स्थिर रहती है।लेकिन "उपयोग किए गए घंटों की संख्या" समय-समय पर विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है, जैसे कि बिजली, पूंजी या श्रम की उपलब्धता। इस तरह के बदलावों के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि किसी भी समय अंतराल के लिए कारखाने का वास्तविक उत्पादन एसीपी से कम है, इसलिए, धारा 3 ए (4) के तहत यह घोषित किया जाता है कि एक निर्धारिती अपने कारखाने के वास्तविक उत्पादन का निर्धारण करने का हकदार है यदि यह एसीपी से कम है। धारा 3 ए (4) के तहत प्रदान किया जाने वाला ऐसा अवसर निर्धारिती के लिए समय-समय में उपलब्ध एक आवर्ती अवसर है।निर्धारिती द्वारा देय शुल्क की राशि का निर्धारण एक बार का मामला नहीं है।इस तरह का निर्णय समय-समय पर किया जाना चाहिए।इसलिए, मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक अवधि के लिए वास्तविक उत्पादन की स्थापना के लिए साक्ष्य रखने का अवसर समय-समय पर निर्धारिती को उपलब्ध होना चाहिए।[पारस 42,43] [1017-ई-एच; 1018-ए]

7. नियम 96 जेडपी (3) उन निर्धारिती के लिए शुल्क के मूल्यांकन के संदर्भ में प्रासंगिक है जो मासिक आधार पर उत्पाद शुल्क के भुगतान का विकल्प चुनते हैं, ऐसे



निर्धारिती द्वारा देय शुल्क मीट्रिक टन में रु.300 x एसीपी होगा।नियम 96 जेडपी (3) में कहा गया है कि नियम 96 जेडपी (3) के तहत योजना (शुल्क की रियायती दर) का लाभ उठाने के इच्छुक निर्धारिती को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना आवश्यक है। नियम उस समय के बारे में मौन है जब इस तरह के आवेदन की आवश्यकता होती है। लेकिन उप-नियम (3) उस समय को निर्धारित करता है जिसके भीतर शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक है, अर्थात्, "प्रत्येक महीने की शुरुआत में" और "प्रत्येक महीने की दसवीं तारीख तक नवीनतम"। यह संभव है कि पूर्वनिर्धारित मामले में एक निर्धारिती किसी दिए गए समय पर उप-नियम (3) के संदर्भ में गणना किए गए मौद्रिक आधार पर शुल्क का भुगतान करने के लिए चुनता है, लेकिन कुछ महीनों बाद (उस मामले के लिए एक महीने बाद भी), विभिन्न वैध कारणों से, उत्पादन (निर्धारिती कारखाने के) एसीपी के काफी नीचे गिर सकता है। यह संभव है कि कुछ मामलों में निर्धारिती के नियंत्रण से बाहर के कारणों से विनिर्माण गतिविधि पूरी तरह से बंद हो सकती है। यदि नियम 96 जेड पी के तहत किसी कर निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अनंत काल के लिए अच्छा माना जाता है, तो यह न केवल अतार्किक परिणामों की ओर ले जाएगा, बल्कि किसी कर योग्य घटना को बताए बिना करों के असंवैधानिक संग्रह की ओर भी ले जाएगा। नियम निर्धारिती को नियम 96 जेडपी (3) की योजना से बाहर निकलने से नहीं रोकता है। अग्रिम शुल्क का भुगतान करके एक महीने के लिए योजना का लाभ उठाने के बाद, यदि निर्धारिती अपने एसीपी के बराबर माल का उत्पादन करने में समर्थ नहीं है, तो नियम निर्धारिती को उत्पादन की उस मात्रा पर शुल्क की रियायती दर (अगले महीने के लिए) का लाभ उठाना जारी रखने के लिए मजबूर नहीं करता है जिसे वह प्राप्त करने में असमर्थ है। निर्धारिती के पास नियम 96 जेडपी (जे) के अनुसार उच्च दर में लेकिन वास्तविक उत्पादन में शुल्क

का भुगतान करने का विकल्प होना चाहिए:उन निर्धारिती के लिए जिन्होंने उप-नियम (1) के अनुसार उच्च दर में शुल्क का भुगतान करने का विकल्प चुना, धारा 3 ए (4) का लाभ उपलब्ध है।[पारस 44-47] [1018-बी-एच;1019-ए-बी।

8. वीनस कास्टिंग्स और सुप्रीम स्टील्स में इस अदालत के दो निर्णयों को देखते हुए प्रतिवादी के लिए यह तर्क दिया जाता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 जेडपी के उप-नियम (3) के अधिकारों के बारे में प्रश्न अब एकीकृत नहीं है। प्रतिवादी द्वारा यह भी निवेदन जाता है कि यह अदालत पहले ही घोषणा कर चुका है कि निर्धारिती जो उप-नियम (3) के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए एक बार विकल्प चुनता है, वह अपनी पसंद पर वापस नहीं जा सकता है।उपर्युक्त दोनों मामलों में, यह अदालत केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 जेड ओ (3) पर विचार कर रहा था।न तो नियम 96 जेड पी (3) के अधिकार और न ही इसकी व्याख्या वास्तव में इनमें से किसी भी मामले में इस अदालत के विचार के लिए नहीं थी। हालांकि, फेनस कास्टिंग्स में पैरा 9 में नियम 96 जेड पी का एक संदर्भ दिया गया था और इस अदालत ने कहा कि "नियम 96 जेड ओ और 96 जेड पी क्रमशः सिल्लों और बिलेट और गर्म पुनः रोल किए गए उत्पादों के निर्माता द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करते हैं।इन प्रावधानों के तहत परिकल्पित योजना समान है।यह निष्कर्ष कि दोनों नियमों की योजना समान है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।नियमों के बीच व्यापक समानताएं हैं लेकिन वे समान नहीं हैं। [पारस 48-50] [1019-सी-एफ]

9. वीनस कास्टिंग्स में, इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त दोनों नियमों में "निर्धारिती के विकल्प पर अपनाई जाने वाली दो वैकल्पिक प्रक्रियाओं" की योजना है और यह निष्कर्ष निकाला कि "निर्माता, यदि उन्होंने अपने विकल्प पर नियम 96 जेड ओ (3) के तहत प्रक्रिया का लाभ उठाया है, तो अधिनियम की धारा

3 ए (4) के तहत उत्पादन क्षमता के निर्धारण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसे विशेष रूप से बाहर रखा गया है", यह अदालत केवल नियम 96 जेड ओ (3) के साथ व्यवहार करता है, लेकिन नियम 96 जेड पी (3) के साथ नहीं। दूसरा, अधिनियम की धारा 3 ए (4) कारखाने की उत्पादन क्षमता के निर्धारण से संबंधित नहीं है। यह केवल निर्धारिती के यह स्थापित करने के अधिकार से संबंधित है कि ए. सी. पी. के निर्धारण के बावजूद, प्राप्त वास्तविक उत्पादन ए.सी.पी. निर्धारित से कम है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि "यदि संपूर्ण अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ा जाता है तो यह उद्देश्य इंगित करता है और वह उद्देश्य नियमों द्वारा पूरा किया जाता है, तो इसे अधिनियम के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र में नहीं कहा जा सकता है।" कानून के इस तरह के कथन का पूर्ववर्ती या कानूनों की व्याख्या के किसी भी तय किए गए सिद्धांतों में कोई आधार नहीं है। दूसरी ओर, यह अधिकारियों की एक लंबी सुलझी हुई पंक्ति के साथ संघर्ष में है कि अधीनस्थ कानून जो मूल अधिनियम के साथ संघर्ष में है, अस्थिर है। [पारस 51,52] [1020-ए-बी, एफ-एच; 1021-ए]

10. सुप्रीम स्टील्स में निर्णय तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था। नियम 96 जेड ओ के अधिकार सीधे सुप्रीम स्टील्स में जारी किए गए थे। वीनस कास्टिंग्स में इस अदालत ने कहा कि "इन कार्यवाहियों में नियमों के प्रावधानों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन उनकी व्याख्या और अनुप्रयोग की जांच की जानी चाहिए।" हालांकि, सुप्रीम स्टील्स के न्यायाधीशों ने राय दी कि विवाद को फेनस कास्टिंग्स में इस अदालत के निर्णय से अंततः सुलझा लिया गया था। उपर्युक्त दो निर्णयों में विभिन्न समस्याओं के अलावा, नियम 96 जेडपी (3) के तहत नियोजित भाषा में अंतर हैं और यह योजना नियम 96 जेड ओ (3), की योजना के तहत अपनाई गई योजना से अलग प्रतीत होती है। [पैरा 53,54] [1021-बी-सी]

11. नियम 96 जेड ओ गैर-मिश्र धातु इस्पात सिल्लियों और बिलेट के निर्माण पर उत्पाद शुल्क के लेवी, मूल्यांकन और संग्रह से संबंधित है। ऐसी वस्तुओं पर शुल्क रु.750-प्रति मीट्रिक टन की दर से देय है, उप-नियम (3) उन निर्माताओं के मामलों में प्रति माह 5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि का शुल्क और संग्रह निर्धारित करता है जिनकी कुल भट्टी क्षमता तीन मीट्रिक टन है यदि उनके कारखाने स्थापित हैं। हालांकि, ऐसी योजना निर्धारिती के विकल्प पर उपलब्ध है, दूसरे शब्दों में एक निर्माता के पास उस महीने के लिए अपने वास्तविक उत्पादन की परवाह किए बिना, निर्माता के वास्तविक उत्पादन के रु.750-प्रति मीट्रिक टन की दर से शुल्क का भुगतान करने के बजाय दो किशतों में 5 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होता है। उक्त उप-नियम में तीन मीट्रिक टन की क्षमता कारखाने की क्षमता प्रति दिन या प्रति माह या प्रति वर्ष है या नहीं, यह नियम की भाषा से बहुत स्पष्ट नहीं है। अभिव्यक्ति को नियमों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। [पैरा 55] [1021-डी-ई; 1022-ए]

12. नियम 96 जेडपी (3) पर आते हुए, यह नियम के तहत आने वाले निर्धारिती को रु.300 प्रति मीट्रिक टन की रियायती दर पर शुल्क का भुगतान करने का विकल्प भी प्रदान करता है, जो उन निर्धारिती के दायित्व के विपरीत है जो प्रति मीट्रिक टन रु.400 का भुगतान करने के लिए उप-नियम (3) के तहत प्रक्रिया का लाभ उठाने का विकल्प नहीं चुनते हैं। लेकिन निर्धारिती के दोनों वर्गों को कारखाने के एसीपी पर गणना किए गए कुल शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। जबकि जो लोग उप-नियम (3) के तहत कर की कम दर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, वे हर महीने कर का भुगतान करते हैं और जो लोग उप-नियम (3) के तहत योजना का लाभ उठाने का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें शुल्क के वास्तव में देय होने के लंबे समय बाद कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है जैसा कि उप-नियम (1) और (2) के

तहत संकेत दिया गया है। नियम 96 जेड ओ (3) और 96 जेड पी (3) के बीच एकमात्र समानता यह है कि दोनों नियम उन निर्धारित के मामलों में अधिनियम की धारा 3 ए (4) के तहत प्रक्रिया के लाभ को समाप्त करने का प्रयास करते हैं जो उप-नियम (3) के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने का विकल्प चुनते हैं जो नियम 96 जेड ओ और 96 जेड पी के तहत प्रदान किए गए शुल्कों के संग्रह और शुल्क के सामान्य नियमों के अपवाद हैं। इसलिए, यह प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल है कि यह मुद्दा वीनस कास्टिंग्स और सुप्रीम स्टील्स में इस अदालत के फैसलों द्वारा कवर किया गया है। इन दोनों निर्णयों के लिए आगे की जांच की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुप्रीम स्टील्स तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है, यह उचित माना जाता है कि कानून के प्रश्न का निपटारा उचित संख्या वाली पीठ द्वारा किया जाए। [पारस 56-58] [1022-बी-एफ]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त बनाम वीनस कास्टिंग्स (पी) ढक्कन। (2000) 4 एससीसी 206:[2000] 2 एस. सी. आर. 988; भारत संघ और अन्य बनाम सुपरनी स्टील्स और जनरल मिल्स और अन्य (2001) 9 एस. सी. सी. 645; समेकित कॉफी ढक्कन। एक अन्य बनाम कॉफी बोर्ड, बेंगलोर (4980) 3 एस. सी. सी. 358:[1980] 3 एस. सी. आर. 625; कृषि बाजार समिति बनाम शालीमार केमिकल वर्क्स ढक्कन। (1997) 5 एससीसी 516:[1997] 1 पूरक। एस. सी. आर. 164 ~ संदर्भित,

मामला कानून संदर्भ

[1997] 1 पूरक। एस. सी. आर. 164

संदर्भित

पैरा 19

[1980] 3 एस. सी. आर. 625	संदर्भित	पैरा 31
[2000] 2 एस. सी. आर. 988	संदर्भित	पैरा 48
(2001) 9 एस. सी. सी. 645	संदर्भित	पैरा 48

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार ; दीवानी याचिका सं 7823/2014

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलोर के डब्ल्यू.ए. क्रमांक 325/2006 में पारित  
निर्णय और आदेश दिनांकित 27.09.2013 से

के साथ

सी. ए. सं. 7825 और 7824/2014

श्रीमती नलिनी चिदंबरम, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक आनंद, आदित्य भट्टाचार्य,  
आनंद के., विक्टर दास, एम. पी. देवनाथ, योगेंद्र, विकास मेहता, सुश्री अनुश्री मेनन,  
अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती निशा बागची, एच. आर. राव, सुश्री पूजा  
शर्मा, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति चेलामेश्वर,जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. ये तीनों अपीलें तथ्यात्मक रूप से आपस में जुड़ी हुई हैं और कानून का एक  
सामान्य प्रश्न भी उठाती हैं।

2. सिविल अपील मेसर्स भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अपीलकर्ताओं के  
पास मूल रूप से कर्नाटक राज्य में स्थित तीन (3) औद्योगिक इकाइयाँ (हॉट री-रोलिंग  
स्टील मिल्स) थीं। इसके बाद, उन इकाइयों में से दो का अधिग्रहण अपीलार्थियों द्वारा  
इस समूह की अन्य दो अपीलों में किया गया।अधिग्रहण का अधिक विवरण इस निर्णय

के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता है।

3. इन अपीलार्थियों की तीन औद्योगिक इकाइयों द्वारा की जाने वाली उत्पादन गतिविधि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (इसके बाद अधिनियम) के तहत उत्पाद शुल्क लगाने के अधीन है।

धारा 3 जहाँ तक इस निर्णय के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, प्रासंगिक समय पर पढ़िए:

“खंड 3.केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क लगाए जाएंगे।- (1) वहाँ शाट! ऐसी रीति में अधिरोपित और संग्रहित किया जाए जो विहित की जाए -

(क) भारत में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में निर्धारित दरों पर उत्पाद शुल्क अधिनियम की मूल प्रभार धारा है।

4. हालांकि, वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 3 ए के तहत। 2008 के अधिनियम 18 द्वारा, धारा. 79 (डब्ल्यू. ई. एफ. 10-5-2008)।इससे पहले धारा 3 ए को 1956 के अधिनियम 81 द्वारा जोड़ा गया था। 2 (डब्ल्यू. ई. एफ., 22-12-1956) और 1960 के अधिनियम 58, एस.2 और एस. आई (डब्ल्यू. ई. एफ. 26-12-1960) और 1997 के अधिनियम 26, सेक द्वारा फिर से जोड़ा गया था। 81 (डब्ल्यू. एट.14-5-1997) और 2000 के अधिनियम 10, धारा द्वारा संशोधित किया गया था। 93 (वी. ई. एफ., 1-4-2000) और 2001 के अधिनियम 14, धारा द्वारा फिर से हटा दिया गया था। 121 (वी. एफ.11-5-2001)..अधिनियम में पेश किया गया।,

“धारा 3 ए। उत्पाद शुल्क लगाने के लिए कारखाने की उत्पादन

की वार्षिक क्षमता का निर्धारण।—

(1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्र सरकार, किसी निर्दिष्ट विवरण की उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसी वस्तुओं या ऐसे अन्य कारकों के संबंध में शुल्क की चोरी की सीमा, जो प्रासंगिक हो, की राय है कि राजस्व के हित की रक्षा करना आवश्यक है, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित वस्तुओं के रूप में ऐसी वस्तुओं को निर्दिष्ट करें और इस धारा के प्रावधानों के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया और एकत्र किया जाएगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के तहत कोई अधिसूचना जारी की जाती है, केंद्र सरकार, नियमों द्वारा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा उत्पादन की वार्षिक क्षमता, या उस कारखाने की उत्पादन की वार्षिक क्षमता से संबंधित ऐसे कारक या कारकों के निर्धारण के लिए प्रावधान कर सकती है जिसमें ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन की ऐसी वार्षिक क्षमता को ऐसे कारखाने द्वारा ऐसी वस्तुओं का वार्षिक उत्पादन माना जाएगा:

बशर्ते कि जहां अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन करने वाला कारखाना वर्ष के केवल एक भाग के दौरान संचालित होता है, वहां उसके उत्पादन की गणना उत्पादन की वार्षिक क्षमता के आनुपातिक आधार में की जाएगी।



(3) अधिसूचित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क उस दर पर लगाया जाएगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे और उस तरीके से एकत्र किया जाए जो निर्धारित किया जाए:

बशर्ते कि, जहां अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखाने ने सात दिनों से कम की किसी निरंतर अवधि के दौरान अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया है, तो आनुपातिक आधार पर गणना की गई शुल्क को ऐसी अवधि के संबंध में समाप्त कर दिया जाएगा यदि ऐसी वस्तुओं का निर्माता ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो निर्धारित की जाएं।

(4) जहां कोई निर्धारिती दावा करता है कि उसके कारखाने में अधिसूचित वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन उप-धारा (2) के तहत निर्धारित उत्पादन से कम है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, निर्धारिती को अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, वास्तविक उत्पादन का निर्धारण करेगा और उप-धारा (3) में निर्दिष्ट दर पर ऐसे वास्तविक उत्पादन के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा देय शुल्क की राशि का पुनर्निर्धारण करेगा।

(5) जहां केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त उप-धारा (4) के तहत वास्तविक उत्पादन निर्धारित करता है, वहां पहले में भुगतान की गई शुल्क की राशि, यदि कोई हो, को इस तरह में पुनर्निर्धारित शुल्क के खिलाफ समायोजित किया जाएगा और यदि पहले में भुगतान किया गया शुल्क इस तरह में पुनर्निर्धारित शुल्क में कम हो जाता है, या

उसमें अधिक है, तो निर्धारिती, यथास्थिति, कमी का भुगतान करेगा या धनवापसी का हकदार होगा।

(6) इस धारा के प्रावधान उत्पादित या निर्मित वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे, -

(i) एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया गया; या

(ii) सौ प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम द्वारा और भारत में बेचे जाने की अनुमति।

स्पष्टीकरण 1.-- संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचित वस्तुओं में देय उत्पाद शुल्क को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के तहत ऐसी वस्तुओं में देय उत्पाद शुल्क माना जाएगा, जिसे उस समय लागू किसी भी अधिसूचना के साथ पढ़ा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "मुक्त व्यापार क्षेत्र" और "सौ प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम" अभिव्यक्तियों के अर्थ धारा 3 में दिए गए हैं।" [जोर दिया गया]

धारा 3 ए अधिनियम की धारा 3 के तहत विचारित लेवी और संग्रह की योजना के अनुसार के अलावा वस्तुओं और लेवी के एक निश्चित वर्ग की पहचान और ऐसी वस्तुओं में उत्पाद शुल्क के संग्रह को अधिकृत करती है। धारा 3 ए की भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि संसद का मानना था कि वस्तुओं के कुछ वर्गों के निर्माता उत्पाद

शुल्क के भुगतान से बच रहे हैं।[टी ने भारत सरकार को उन वस्तुओं की पहचान करने के लिए अधिकृत किया, जिनके निर्माता उत्पाद शुल्क की चोरी का सहारा ले रहे हैं। धारा 3 ए (1) में निर्धारित किया गया है कि ऐसी पहचान की गई वस्तुओं को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना है (इसके बाद "अधिसूचित वस्तुएं")। धारा 3 ए (3), जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर थी, यह निर्धारित करती है कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शुल्क की दर और उसके संग्रह की विधि और तरीके को निर्दिष्ट कर सकती है।

दूसरे शब्दों में, धारा 3 के अनुसार शुल्क की दरों के निर्धारण और शुल्क देयता के मूल्यांकन की प्रक्रिया और ऐसे निर्धारित शुल्क के संग्रह के तरीके के बावजूद, भारत सरकार को धारा 3 ए के तहत शुल्क की विभिन्न दरों और अधिसूचित वस्तुओं पर निर्धारण और शुल्क के संग्रह के विभिन्न तरीकों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

उप-धारा (2) के तहत, भारत सरकार को उस कारखाने की "उत्पादन की वार्षिक क्षमता" (इसके बाद ए. सी. पी.) या "ए. सी. पी. के लिए प्रासंगिक कारकों" के निर्धारण के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया था जिसमें अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ए. सी. पी. का निर्धारण "केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त" द्वारा किया जाना आवश्यक है।इसने आगे घोषणा की कि एक कारखाना जहां ए. सी. पी. निर्धारित किया जाता है, उसे वार्षिक रूप से अपने ए. सी. पी. के बराबर मात्रा में अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए माना जाएगा।

उप-धारा (4) में कहा गया है कि ऐसे मामले में जहां एक निर्धारिती दावा करता है कि उसके कारखाने का वास्तविक उत्पादन एसीपी से कम है, निर्धारिती उचित साक्ष्य

प्रस्तुत करके अपने कारखाने में अधिसूचित वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन के निर्धारण की मांग करने का हकदार है। इस तरह का दावा किए जाने पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से निर्धारिती के कारखाने के वास्तविक उत्पादन का निर्धारण करने और "इस तरह के वास्तविक उत्पादन के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा देय शुल्क की राशि का पुनर्निर्धारण करने" की आवश्यकता होती है।"

5. मान लीजिए, तीनों अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित सामान एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत "गैर-मिश्र धातु इस्पात गर्म पुनः लुढ़का हुआ उत्पाद" के रूप में वर्णित हैं और वे प्रासंगिक समय पर अधिसूचित वस्तुएं थीं।

6. अधिनियम की धारा 3 एक्यू के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए नियमों का एक समूह तैयार किया गया, जिसे हॉट री-रोलिंग स्टील मिल्स वार्षिक क्षमता अधिसूचना नियम, 1997 (इसके बाद "1997 के नियम") के रूप में जाना जाता है।

7. एक महीने बाद, 30.8.1997 पर, नियम 5 जो वर्तमान मामले में विवाद का मूल है, उक्त नियमों में सम्मिलित किया गया:

"5. यदि किसी मिल के संबंध में नियम 3 के उप-नियम (3) के सूत्र द्वारा निर्धारित वार्षिक क्षमता वित्तीय वर्ष के दौरान मिल के वास्तविक उत्पादन से कम है, तो इस प्रकार निर्धारित वार्षिक क्षमता को वित्तीय वर्ष के दौरान मिल के वास्तविक उत्पादन के बराबर माना जाएगा।"  
{जोर दिया गया] नियम के सही अर्थ और उद्देश्य की जांच बाद में की जाएगी।

8. इस तथ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के रूप में जाने जाने वाले नियमों का एक समूह तैयार किया गया था। उक्त नियमों के नियम 96 जेडपी में उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के विभिन्न शीर्षों के तहत आने वाले 'गैर-मिश्र धातु इस्पात गर्म पुनः रॉल वाले उत्पादों' के निर्माताओं द्वारा पालन की जाने वाली एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त नियम 1944 के नियमों के अध्याय 11 में आता है। अध्याय 11 को नियम डब्ल्यू. ई. एफ. 01.08.1997 में जोड़ा गया था।

9. धारा 3 ए (3) केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा उस दर को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करती है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचित वस्तुओं पर लगाया जा सकता है। जाहिर है, यह धारा 3 ए (3) के तहत शक्ति का प्रयोग है, नियम 96 जेडपी को अपीलकर्ता द्वारा निर्मित माल में प्रति मीट्रिक टन की एक निश्चित दर निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। यह नियम 96 जेडपी (1) और (3) के तहत एक ही विवरण के तहत आने वाली वस्तुओं पर अलग-अलग दरों पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान करता है, जो शुल्क के भुगतान के समय के बारे में निर्धारिती की पसंद पर निर्भर करता है, नियम 96 जेडपी रु.300-प्रति मीट्रिक टन की रियायती दर पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रयास करता है।

10. नियम 96 जेडपी निर्दिष्ट वस्तुओं के मूल्य के आधार पर नहीं बल्कि उत्पादन की मात्रा के आधार पर शुल्क निर्धारित करता है। यह निर्माता द्वारा चुने गए शुल्क के भुगतान के तरीके के आधार पर विभिन्न दरों पर शुल्क लगाने और संग्रह करने को भी अधिकृत करता है। दूसरे शब्दों में, नियम 96 जेडपी नियम के दायरे में आने वाले माल के निर्माताओं के दो वर्गों का निर्माण करता है, हालांकि निर्माताओं के

दोनों वर्ग एक ही विवरण के माल का उत्पादन करते हैं। एक वर्ग जो मासिक आधार में शुल्क का भुगतान करने का विकल्प चुनता है (उप-नियम (3) के तहत आता है) और दूसरा वर्ग नियम 962 जेडपी के विभिन्न अन्य उप-नियमों के तहत अन्यथा निर्दिष्ट तरीके से शुल्क का भुगतान करता है।

11. निर्विवाद रूप से, नियम 96 जेड पी यहाँ अपीलार्थियों के उत्पादों पर लागू होता है। हमारे उद्देश्य के लिए यह ध्यान दें पर्याप्त है कि नियम 96 जेडपी (1) के तहत "नियम 96 जेडपी (1) गैर-मिश्र धातु इस्पात गर्म पुनः लुढ़का हुआ उत्पादों का निर्माता जो उप-शीर्षक संख्या..... के तहत आता है।- केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अनुसार, 1 करोड़ रुपये की दर से गणना की गई राशि का भुगतान करें। 400/- प्रति मीट्रिक टन अपने कारखाने से उत्पादों की निकासी पर इस शर्त के अधीन कि शुल्क देयता की कुल राशि की गणना की जाएगी और निम्नलिखित तरीके से भुगतान किया जाएगा," नियम 96 जेड पी के दायरे में आने वाले माल के निर्माता को रु.400-प्रति मीट्रिक टन की दर से गणना की गई राशि को गैर-मिश्र धातु इस्पात गर्म फिर से रोल किए गए उत्पादों पर डेबिट करना आवश्यक है? उसके कारखाने से माल की निकासी के समय। नियम 96 जेडपी (1) के पैराग्राफ लैंड आई. ई. के तहत, डेबिट किए गए शुल्क के भुगतान का तरीका निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए, 1 प्रतिशत सितंबर, 1997 से 31-मार्च-1998 तक की अवधि के लिए, एक निर्माता को 31 मार्च 1998 तक अपने कारखाने के एसीपी पर रु.400-प्रति मीट्रिक टन की दर से गणना की गई कुल राशि का भुगतान करना आवश्यक है। उप-नियम (1) के अन्य पैराग्राफ का पूरा विवरण इस निर्णय के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

12. उप-नियम (3) के तहत,

“नियम 96 जेडपी (3) इन नियमों में कहीं और निहित कुछ भी होने के बावजूद एक निर्माता, प्रत्येक महीने की शुरुआत में सितंबर, 1997 के पहले दिन से लेकर मार्च, 1998 के 31 वें दिन तक या कोई अन्य वित्तीय वर्ष, जैसा भी मामला हो, कर सकता है। और प्रत्येक महीने के दसवें दिन तक, हॉट री-रोलिंग मिल्स वार्षिक क्षमता निर्धारण नियम, 1997 के नियम 3 के उप-नियम (3) के तहत निर्धारित मीट्रिक टन में वार्षिक क्षमता से गुणा करके रु.300 की दर से गणना की गई राशि के बारहवें हिस्से के बराबर राशि का भुगतान करें और इस तरह से भुगतान की गई राशि को सितंबर, 1997 के पहले दिन से लेकर मार्च, 1998 के तीसरे दिन तक की अवधि के लिए या किसी अन्य वित्तीय वर्ष के लिए, इस शर्त के अधीन कि निर्माता, यदि कोई हो, उप-धारा (3) के प्रावधान के तहत या उप-धारा (4) के तहत लाभ का लाभ नहीं उठाएगा।

13. कानून के प्रावधानों की इसी पृष्ठभूमि में ये अपीलें हैं निर्णय लेना आवश्यक है।

14. इन सभी अपीलों में संबंधित फैक्ट्रियों के ए.सी.पी विभिन्न आदेशों द्वारा निर्धारित। जाहिर है एसीपी इतना दृढ़ था वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए प्रत्येक कारखाने के वास्तविक उत्पादन से कम। इसलिए, 1997 के नियमों के नियम 5 के तहत निहित आदेश के मद्देनजर एसीपी को वित्तीय वर्ष 1996-1997 के वास्तविक उत्पादन के समान माना गया था।

15. एसीपी के निर्धारण से व्यथित होकर प्रत्येक अपीलकर्ता ने कई कानूनी कार्यवाही की:

1. उन्होंने CESTAT से अपील की;
2. उन्होंने धारा 3 ए की उपधारा (4) के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के

अधिकार का इस्तेमाल किया; और

3. इसके साथ ही, उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में उपर्युक्त नियम 5 की वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएँ दायर कीं।

16. दिनांकित निर्णय द्वारा रिट याचिकाएँ खारिज कर दी गईं कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का 07 .12 .2005। व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने इस मामले को इंद्राकोर्ट अपील के माध्यम से कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच में ले जाया। अपील के तहत निर्णय द्वारा, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपीलों को खारिज कर दिया। इसलिए ये अपीलें.

17. 1997 के नियमों के नियम 5 की वैधता को उच्च न्यायालय और हमारे समक्ष दो आधारों पर चुनौती दी गई है:

1. यह नियम अधिनियम की धारा 3 ए के तहत प्रदत्त प्राधिकार के अधिकार के बाहर है; और

2. यह नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

क्योंकि नियम निर्माताओं के दो वर्ग बनाता है:-

i) जिनकी एसीपी वित्तीय वर्ष 1996-97 में उनके वास्तविक उत्पादन से अधिक निर्धारित की गई है। (ii) जिनकी एसीपी वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए उनके वास्तविक उत्पादन से कम निर्धारित की गई है; और 1997 के नियमों के दायरे में आने वाले निर्माताओं की उपरोक्त दो श्रेणियों में से दो पर अतार्किक कर का बोझ डालता है।

18. हम सबसे पहले इस दलील पर विचार करेंगे कि 1997 के नियमों का नियम 5 अधिनियम की धारा 3 ए के अधिकार क्षेत्र अधिकारित है।



यह तर्क दिया जाता है कि नियम 5 एक काल्पनिक कथा बनाता है जब यह निर्धारित करता है:

"..... इस प्रकार निर्धारित वार्षिक क्षमता वित्तीय वर्ष के दौरान मिल के वास्तविक उत्पादन के बराबर मानी जाएगी।"[जोर दिया गया]

19. अपीलार्थियों के अनुसार, अधिनियम की धारा 3 ए (2) स्वयं एसीपी का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक कल्पना पैदा करती है, जबकि भारत सरकार को एसीपी के निर्धारण के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। इसलिए, नियम एक और कल्पना निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अपीलकर्ताओं ने कृषि बाजार समिति बनाम शालीमार केमिकल वर्क्स लिड, (1997) 5 एस. सी. सी. 516 में रिपोर्ट किए गए इस अदालत के निर्णय पर इस प्रस्ताव के लिए भारी निर्भरता रखी।

20. दूसरी ओर, प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि नियम 5 हालांकि शाब्दिक रूप से एक कल्पना का निर्माण करता प्रतीत होता है, सार में यह केवल एसीपी के निर्धारण के लिए प्रासंगिक कारक को निर्धारित करता है और इसलिए, स्पष्ट रूप से इसका अधिकार है।

21. इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए, अधिनियम की धारा 3 ए की योजना, उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों और उस शरारत की जांच करना आवश्यक है जिसे संसद ने नियंत्रित करने की कोशिश की थी। धारा 3 ए को अधिनियमित करते समय। इस संदर्भ में हमें अधिनियम की सामान्य योजना को ध्यान में रखना चाहिए।

22. अधिनियम की धारा 3, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर मौजूद थी, भारत में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क पर उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने के लिए अधिकृत करती है। अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत "उत्पाद शुल्क" शब्द को

परिभाषित किया गया है। प्रासंगिक समय पर, यह इस प्रकार हैः;

“धारा 2 (घ)।”उत्पाद शुल्क का अर्थ है केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुएं जो उत्पाद शुल्क के अधीन हैं और इसमें नमक भी शामिल है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के तहत समय-समय पर वस्तुओं के विभिन्न वर्गों के लिए शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। अधिनियम की धारा 4 उन निर्माताओं के शुल्क दायित्व के निर्धारण के उद्देश्य से माल के मूल्य के निर्धारण की विधि और तरीका निर्धारित करती है जो उन वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करते हैं जो उनके मूल्य के अनुसार शुल्क के लिए देय हैं।

23. निर्मित वस्तुओं की मात्रा का निर्धारण उत्पाद शुल्क एकत्र करने के लिए एक आवश्यक अभ्यास है, क्योंकि उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने के लिए कर योग्य घटना वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन है। इसलिए, निर्मित वस्तुओं की वास्तविक मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता है। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम ऐसे व्यक्ति की कर योग्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति (निर्माता) द्वारा किए गए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन/निर्माण की मात्रा निर्धारित करने के लिए अलग-अलग तरीके निर्धारित करते हैं।

24. संसद ने समय-समय पर इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कुछ उत्पादक/उत्पादक अपने द्वारा किए गए माल के वास्तविक उत्पादन/निर्माण की मात्रा की जानकारी को दबा कर शुल्क से बच रहे हैं। इसलिए, धारा 3 ए पेश की गई जिसने अधिसूचित वस्तुओं पर शुल्क लगाने, मूल्यांकन करने और उत्पाद शुल्क के संग्रह के

एक अलग तरीके को अधिकृत किया। धारा 3 ए की योजना के तहत, उत्पादित/निर्मित अधिसूचित वस्तुओं की वास्तविक मात्रा की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता को यह बताते हुए दूर किया जाता है कि कारखाने के एसीपी को उत्पाद शुल्क के लेवी और संकलन के उद्देश्य से कारखाने का वार्षिक उत्पादन माना जाता है।

25. 1997 के नियमों ने उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा एसीपी का निर्धारण किया जाना है, नियम 3 ने एसीपी के निर्धारण के लिए उसमें उल्लिखित विभिन्न कारकों के आधार पर एक सूत्र निर्धारित किया। अपीलार्थियों को ए. सी. पी. के निर्धारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के बारे में कोई शिकायत नहीं है। उनकी एकमात्र शिकायत नियम 5 के खिलाफ है जो आदेश देता है कि नियम 3 के अनुसार निर्धारित एसीपी को नियम 5 के तहत उल्लिखित परिस्थितियों में खारिज कर दिया जाए।

26. अपीलकर्ता ने निवेदन कि धारा 3 ए (2) यह घोषणा करके एक कानूनी कल्पना पैदा करती है कि कारखाने का वार्षिक उत्पादन जिसमें अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उस कारखाने के एसीपी के समान है। नियम 5 एक और कल्पना पैदा करता है जो या तो धारा 3 ए द्वारा अधिकृत नहीं है या एक गैर-संप्रभु कानून बनाम वाले निकाय के लिए अनुमेय नहीं है जो एक अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ कानून बनाता है। हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने धारा 3 ए (2) की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी।

27. अपीलकर्ताओं ने कृषि बाजार समिति के कंडिका 28 पर भारी निर्भरता रखी।

“28. जिस सरकार को धारा 33 के तहत नियम बनाने की शक्ति दी गई थी और जिस समिति को धारा 34 के तहत उपनियम बनाने की

शक्ति दी गई थी, उसने यह प्रावधान करते हुए "अनुमान" का दायरा बढ़ाया कि यदि किसी अधिसूचित कृषि उपज को अधिसूचित क्षेत्र के भीतर तौला, मापा या गिना जाता है, तो उसे उस क्षेत्र में बेचा या खरीदा गया माना जाएगा। इस प्रकार कानूनी कल्पना का निर्माण विधायी नीति से परे है। इस तरह की कानूनी कल्पना केवल विधायिका द्वारा बनाई जा सकती है न कि नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रतिनिधि द्वारा। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के साथ पूरी तरह से सहमत हैं कि नियम 74 (2) और उपनियम 24 (5) अधिनियम के दायरे में बाहर हैं और इसलिए, अधिकार में बाहर हैं। मूल्यांकन प्राधिकारी और अपील और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा इन प्रावधानों पर रखी गई निर्भरता पूरी तरह से गलत थी और वे केवल अधिसूचित क्षेत्र समिति के भीतर "कोपरा" के वजन के आधार पर यह ठहराने में न्याय हित नहीं हैं कि बिक्री का लेनदेन उस बाजार क्षेत्र में हुआ था।"

28. नियम 5 के संबंध में अपीलार्थियों का तर्क दो गुना प्रतीत होता है: (i) एक कानूनी कल्पना (प्रावधान मानते हुए) केवल कानून द्वारा बनाई जा सकती है, लेकिन अधीनस्थ कानून द्वारा नहीं; और (ii) अन्यथा अधीनस्थ कानून द्वारा बनाई गई कल्पना भी मूल अधिनियम में प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकती है।

"नियम 5 को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई थी:-  
(अपीलार्थी की लिखित प्रस्तुतियाँ) ए. धारा 3 ए (2) वार्षिक उत्पादन क्षमता को वास्तविक उत्पादन मानती है और निर्माता को वास्तविक उत्पादन के संदर्भ के बिना वार्षिक उत्पादन क्षमता पर शुल्क का

भुगतान करना पड़ता है।

लेकिन नियम 5 एक और धारणा प्रस्तुत करता है कि यदि 1996-97 उत्पादन नियम 3 के अनुसार निर्धारित उत्पादन क्षमता से अधिक है तो 1996-97 उत्पादन को वास्तविक उत्पादन माना जाएगा।

एक अधीनस्थ विधान एक डीमिंग प्रावधान पेश नहीं कर सकता है और वह भी पूर्ण विधान में डीमिंग प्रावधान के विपरीत। धारा 3 ए के तहत वैधानिक धारणा एक सीमित प्रकृति की है और एक राजकोषीय कानून होने के नाते इसका कड़ाई से इस अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए कि कोई भी कारखाना जो अधिनियम द्वारा विचार नहीं किया गया है, उत्पाद शुल्क लगाने के लिए एक धारणा को बढ़ाने के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता है। प्रत्यायोजित विधान होने के नाते प्रतिनिधि जिसे सहायक नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, उसे अधिनियम या उसके तहत निर्धारित नीति के दायरे में काम करना होगा। नियम बनाने के अधिकार के तहत प्रतिनिधि अधिनियम के दायरे में आने वाले क्षेत्र में कानून नहीं बना सकता है और उसे अधिनियम के कार्यान्वयन के तरीके में खुद को बदलना होगा। नियम 3 के तहत कानूनी कल्पना का निर्माण नियम 3 में निर्दिष्ट सूत्र के तहत निर्धारित उत्पादन की क्षमता पर कुछ अधिसूचित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए विधायी नीति के दायरे से बाहर है। इस तरह की कानूनी कल्पना केवल एक विधायिका द्वारा बनाई जा सकती है न कि नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग में एक प्रतिनिधि द्वारा। इसके अलावा धारा 3 ए (2) केवल केंद्र सरकार को उत्पादन की

वार्षिक क्षमता या उत्पादन की वार्षिक क्षमता के लिए प्रासंगिक ऐसे कारक के निर्धारण के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। धारा 3 ए (2) केंद्र सरकार को उत्पादन की वार्षिक क्षमता पर आगे कानूनी कल्पना बनाने के लिए अधिकृत नहीं करती है जो विशेष रूप से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में है। इस प्रकार नियम 5 में यह कानूनी कल्पना बनाई गई है कि यदि किसी मिल के संबंध में नियम 3 अधिकारातीत 3 में सूत्र द्वारा निर्धारित वार्षिक क्षमता वित्तीय वर्ष के दौरान मिल के वास्तविक उत्पादन से कम है, तो इस प्रकार निर्धारित वार्षिक क्षमता को वित्तीय वर्ष के दौरान मिल के वास्तविक उत्पादन के बराबर माना जाएगा।”

(1997) 5 एस. सी. सी. 516 का संदर्भ दिया जा सकता है।

29. हम कृषि बाजार समिति के अनुच्छेद 28 में इस अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांत से पूरी तरह सहमत हैं।

30. हालाँकि, इस मामले में प्रश्न यह है कि क्या धारा 3 ए (2) और/या नियम 5 वास्तव में कल्पनाएँ पैदा करते हैं। इसे समझने के लिए, धारा 3 ए और नियम 5 के संदर्भ और उद्देश्य है जांच है जानी चाहिए। धारा 3 ए की योजना और उद्देश्य की जांच पहले ही पैरा 20 में की जा चुकी है। नियम 5 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि पूर्ववर्ती चार नियमों के अनुसार निर्धारित ए. सी. पी. वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष निर्धारिती के वास्तविक उत्पादन से कम है, तो ए. सी. पी. का निर्धारण करने वाले प्राधिकरण को नियम। से 4 में निहित प्रक्रिया को लागू करके प्राप्त ए. सी. पी. के आंकड़े को परित्याग करना होगा और वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा प्राप्त वास्तविक उत्पादन को अपनाना होगा। वित्तीय वर्ष 1996-1997 वह वित्तीय वर्ष है जो

1997 के नियमों के बनने से ठीक पहले उस निर्धारिती का ए. सी. पी. होगा।”

31. धारा 3 ए (2) और नियम 5 दोनों में आने वाले शब्द "शाल/माना जाए" एक कल्पना की रचना करते प्रतीत होते हैं।लेकिन हमारी राय में एक सच्चे और उचित निर्माण पर (जैसा कि प्रतिवादी द्वारा सही तर्क दिया गया है) वे एक कानूनी कल्पना नहीं बनाते हैं।समेकित कॉफी लिमिटेड और एनोटिटर बनाम कॉफी बोर्ड, बेंगलोर, (1980) 3 एस. सी. सी. 358 में, यह आयोजित किया गया था:(पृष्ठ 371, पैरा 11)

“..... "डीम्ड" शब्द का उपयोग आधुनिक कानून में विभिन्न अर्थों में किया जाता है और ऐसा नहीं है कि हर बार एक काल्पनिक कथा बनाने के उद्देश्य से एक डीमिंग प्रावधान किया जाता है।जो स्पष्ट है या जो अनिश्चित है उसे शामिल करने के लिए या किसी अधिनियम के उद्देश्य के लिए किसी शब्द या वाक्यांश का एक कृत्रिम निर्माण लागू करने के लिए एक डीमिंग प्रावधान किया जा सकता है जो अन्यथा प्रबल नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक मामले में यह एक प्रश्न होगा कि विधायिका ने किस उद्देश्य के साथ ऐसा डीमिंग प्रावधान किया है, St.Aubyn y में।महान्यायवादी, 1952 अधिनियम 15,53:(1951) 2 AILER 473,498, लॉर्ड रैडक्लिफ ने इस प्रकार देखा:

“"डीम्ड" शब्द का उपयोग आधुनिक विधान में बहुत अधिक किया जाता है।कभी-कभी इसका उपयोग किसी अधिनियम के उद्देश्यों के लिए किसी शब्द या वाक्यांश के कृत्रिम निर्माण को लागू करने के लिए किया जाता है जो अन्यथा प्रबल नहीं होता।कभी-कभी इसका उपयोग संदेह से परे एक विशेष निर्माण को रखने के लिए किया जाता है जो अन्यथा अनिश्चित हो सकता है।कभी-कभी इसका उपयोग एक व्यापक विवरण देने के लिए किया जाता है जिसमें क्या स्पष्ट है, क्या अनिश्चित है और क्या है, सामान्य अर्थों में असंभव है।”

हमारी राय में, धारा 3 ए (2) केवल साक्ष्य के एक नियम का प्रतीक है जो विभाग को कुछ तथ्यों का अनुमान लगाने का आदेश देता है। इस तरह के अनुमान कानून के लिए अज्ञात नहीं हैं। धारा 114 "धारा 114। अदालत कुछ अधिनियमों के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है:- न्यायालय विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है जो उसके अनुसार होने की संभावना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत साक्ष्य का एक नियम लागू किया गया है, जिसके तहत अदालत को किसी भी ऐसे तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में अदालत को लगता है कि ऐसा हुआ होगा-प्राकृतिक घटनाओं आदि के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए। नियम 5 के तहत बनाई गई धारणा चित्रण (डी) "चित्रण (डी) में निहित ओ. एन. सी. के समान है-कि एक ऐसी चीज या स्थिति जो उस अवधि से कम समय के भीतर अस्तित्व में दिखाई गई है जिसके भीतर ऐसी चीजें या स्थितियों का अस्तित्व आमतौर पर समाप्त हो जाता है। अभी भी अस्तित्व में है।" साक्ष्य अधिनियम की धारा 114।

32. कानूनी कल्पना और धारणा "नंदियाल वासुदेव बदवैक बनाम, लता नंदलाल बदवैक और अन्य" के बीच कानून में स्पष्ट अंतर है। (2014) 2 एससीसी 376। "हमें एक कानूनी कल्पना और एक तथ्य की धारणा के बीच के अंतर को समझना चाहिए। कानूनी कल्पना एक ऐसे तथ्य के अस्तित्व को मानती है जो वास्तव में मौजूद नहीं हो सकता है। हालांकि, किसी तथ्य का अनुमान कुछ परिस्थितियों की संतुष्टि पर निर्भर करता है। वे परिस्थितियाँ तार्किक रूप से उस तथ्य की ओर ले जाएंगी जिसे अनुमानित किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 एक कानूनी कल्पना नहीं बनाती है, बल्कि



अनुमान का प्रावधान करती है।" (पैरा 18) "।"आमतौर पर कल्पना और कानूनी धारणा के बीच लिया जाने वाला अंतर कुछ इस प्रकार है: एक कल्पना कुछ ऐसा मानती है जिसे गलत माना जाता है; एक धारणा (चाहे वह निर्णायक हो या खंडन योग्य) कुछ ऐसा मानती है जो संभवतः सच हो सकता है। इस भेद को प्रबलित माना जाता है, जैसा कि खंडन योग्य अनुमान के मामले में किया गया था, क्योंकि इस तरह की धारणा एक तथ्य मानती है जो शायद सच है।" (फुल्लेट, एल. एल., लीगल फिक्शन। इमलिनोइस लॉ पुनर्विलोकन (वॉल्यूम। XXV नंबर 4 दिसंबर 1930) "अनुमान कानूनी कल्पनाओं से निकटता से संबंधित हैं. लेकिन वे अलग तरह से काम करते हैं" (डेल मार, मैक्सिमिलियन, लीगल फिक्शन एंड लीगल चेंज। (संदर्भ में कानून की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका (2013)) "कल्पनाएँ हमेशा वास्तविकता के साथ संघर्ष करती हैं, जबकि धारणाएँ सच साबित हो सकती हैं" (वर्मीर-किन्जली, एनीमेरिके, जैसे कि; द लीगल फिक्शन में डिप्लोमैटिक प्रोटेक्शन, यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ (2007)?, कानूनी कल्पनाएँ विधायिका के जनादेश द्वारा एक कृत्रिम स्थिति पैदा करती हैं।

\*...साबित या संभावित तथ्यों के विपरीत जानबूझकर, कानूनी रूप से और निर्विवाद रूप से तथ्य की धारणा। प्रवर्तन में एक विशेष कानूनी नियम. धारणा कानून द्वारा अनुमत की जा रही है।

वे अदालतों सहित सभी संबंधित लोगों को तथ्यों की वास्तविक स्थिति के विपरीत तथ्यों की एक कृत्रिम स्थिति के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं। जब कानून द्वारा एक कल्पना बनाई जाती है, तो यह किसी के लिए भी यह दलील देने या तर्क देने के लिए खुला नहीं होता है कि कानून द्वारा बनाए गए तथ्यों की कृत्रिम स्थिति सच नहीं है, केवल एक संभव पाठ्यक्रम को छोड़कर यदि उपलब्ध हो तो कल्पना की संवैधानिकता पर प्रश्न उठाना है। यह एक स्थापित कानून है कि केवल संप्रभु

विधायी निकाय ही कानूनी कल्पनाएँ बना सकते हैं, लेकिन एक अधीनस्थ कानून बनाने वाला निकाय नहीं।

33. जबकि अनुमान मुकदमे में कुछ तथ्यों के अस्तित्व या अन्यथा को निर्धारित करने के लिए साक्ष्य के नियम हैं।

“अनुमान अंग्रेजी कानून के अनुसार चार प्रकार के होते हैं।

1. निर्णायक अनुमान। ये दुर्लभ हैं, लेकिन जब वे होते हैं तो वे प्रदान करते हैं कि सबूत के कुछ तरीके विरोधाभास के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

2. ऐसी धारणाएँ जो प्रमाण के बोझ के बारे में सामान्य नियम को प्रभावित करती हैं कि जो पुष्टि करता है उसे साबित करना होगा। जो यह पुष्टि करता है कि एक आदमी मर चुका है, उसे आमतौर पर इसे साबित करना होगा, लेकिन अगर वह दिखाता है कि उस आदमी के बारे में सात साल से नहीं सुना गया है, तो वह सबूत का बोझ अपने विरोधी पर डाल देता है।

3. कुछ धारणाएँ हैं जिनका हालांकि खंडन किया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी कानून द्वारा इन्हें केवल अधिकतम से कुछ अधिक माना जाता है, हालांकि यह कहना किसी भी तरह से आसान नहीं है कि कितना अधिक है। इस तरह की धारणा का एक उदाहरण नियम में मिला जाता है कि हाल ही में चोरी किए गए सामान के कब्जे से यह धारणा बनती है कि मालिक या तो चोर है या प्राप्तकर्ता है।

4. तथ्य की कोरी धारणाएँ, जो तर्कों के अलावा और कुछ नहीं हैं,

जिन्हें न्यायालय अपनी इच्छानुसार कोई भी मूल्य देता है। "

ऐसे निष्कर्ष थे जिन्हें न्यायाधीशों को कुछ मामलों में तथ्यों की कुछ स्थितियों से निकालने का निर्देश दिया गया था, और इन अनुमानों को सबूत के पैमाने में एक निश्चित मात्रा में वजन की अनुमति दी गई थी; इस तरह की धारणा और इस तरह के सबूत पूर्ण प्रमाण के बराबर होते हैं, ऐसे अन्य के लिए आधे-अधूरे, और इसी तरह। \*स्टीफन, जेन्स फिट्जजेर्स, द इंडियन एविडेन्स .-लेट लिथ .-एलएन!एनप्रोडक्शन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ़ ज्यूडिशियल एविडेन्स। (कलकत्ता। ठाकर। स्पिंक एंड कंपनी) अध्याय जेवी पी। 132 हमारे ध्यान में यह कहने के लिए कुछ भी नहीं लाया गया है कि ~ गैर-संप्रभु कानून बनाने वाली संस्था किसी अनुमान वाले साक्ष्य का नियम नहीं बना सकती है। हमारी राय में, अफ्रीकी सांस्कृतिक बाजार समिति इस प्रस्ताव के लिए कोई प्राधिकारी नहीं है कि अधीनस्थ कानून द्वारा एक धारणा नहीं बनाई जा सकती है।

34. साक्ष्य के नियम जों के सिद्धांत हैं जो अदालतों या अन्य निकायों को आदेश देते हैं जिनका कर्तव्य कुछ तथ्यों के अस्तित्व या अन्यथा का निर्धारण करना है। एंग्लो सैक्सन कानूनी प्रणाली यह मानती है कि तथ्यों को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कुछ तथ्यों को मान लेना, यदि ऐसा कानून द्वारा आदेशित हो तो हमेशा होता है हमारी कानूनी प्रणाली द्वारा उन निकायों के लिए स्वीकृत प्रक्रियाओं में से एक माना गया है जिन पर साक्ष्य एकत्र करने का कर्तव्य सौंपा गया है। इसलिए, कानून बनाने वाली संस्थाएं जहां भी उचित समझती हैं वहां अनुमानों को शामिल करते हुए प्रावधान करती हैं। लेकिन ऐसी प्रथाओं की अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त योग्यताएं और सीमाएं हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 अनुमान के कानून के कुछ बुनियादी सिद्धांतों और उन पर सीमाओं का प्रतीक है। तकनीकी रूप से, साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य एकत्र करने की जिम्मेदारी वाले प्रत्येक

निकाय पर लागू हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन प्रावधानों में अंतर्निहित सिद्धांत मूल्यवान मार्गदर्शकों का गठन करते हैं। वे मानव आचरण, घटनाओं के प्राकृतिक पाठ्यक्रम और तर्क आदि के अवलोकन से उत्पन्न न्यायशास्त्र के ठोस सिद्धांतों पर आधारित हैं।

35. अनुमान दो प्रकार के होते हैं, खंडनयोग्य और अकाट्य। आम तौर पर कोई भी अनुमान खंडनयोग्य होता है जब तक कि विधायिका कोई खंडनयोग्य अनुमान न बना ले। यह एक अलग प्रश्न है - क्या एक गैर-संप्रभु कानून-निर्माता संस्था द्वारा एक अचूक धारणा बनाई जा सकती है? उस प्रश्न पर हमारे सामने बहस नहीं की गई है और इसलिए, हम उस प्रस्ताव की जांच नहीं करते हैं।

36. अधिनियम की योजना के तहत, किसी उद्योग (निर्माता) के उत्पादन की वास्तविक मात्रा निर्माता की कर देयता निर्धारित करने के लिए आवश्यक कारकों में से एक है। धारा 3 ए(2) और नियम 5 दोनों अधिसूचित माल का उत्पादन करने वाले कारखाने के उत्पादन की मात्रा के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित हैं। किसी भी निर्माता द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सटीक मात्रा निर्धारित करने के लिए, विभिन्न संभावित तरीके हैं:

1. लगातार मैन्युअल अवलोकन या खाता रखना सबसे बुनियादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की मात्रा निर्धारित की जा सकती है;

2. माल की मात्रा स्थापित करने के लिए एक सांख्यिकीय उपाय को अपनाना:

सांख्यिकीय पद्धति या तो माल के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के उपभोग कारकों या उद्योग द्वारा माल आदि के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत या अन्य ऊर्जा की मात्रा पर आधारित हो सकती है; और

3. निर्माता आदि द्वारा नियोजित मशीनरी से संबंधित तकनीकी डेटा को ध्यान में रखते हुए एक उचित अनुमान लगाकर।

37. अधिनियम की धारा 3 ए सरकार को निर्माताओं के एसीपी निर्धारित करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। यह आगे घोषणा करता है कि इस प्रकार निर्धारित ए. सी. पी. को "ऐसे कारखाने द्वारा ऐसे माल की वार्षिक खरीद माना जाएगा।" दूसरे शब्दों में उप-धारा (2) आदेश देती है कि एक कारखाना जिसका एसीपी उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, यह माना जाना चाहिए कि वह प्रत्येक सफल वर्ष के लिए एसीपी के बराबर माल का समान मात्रा में उत्पादन करता है। प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की घोषणा एक कानूनी कल्पना पैदा करती है या केवल एक धारणा (साक्ष्य का नियम)?

38. हम पहले ही देख चुके हैं कि परिभाषा के अनुसार "कल्पना हमेशा वास्तविकता के साथ संघर्ष करती है जबकि धारणा सच साबित हो सकती है।" [इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि किसी काल्पनिक कथा का साक्ष्य द्वारा खंडन किया जाए। निर्माता के वार्षिक उत्पादन के संबंध में धारा 3 ए (2) से बहने वाले विश्वास का खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करके किया जा सकता है। धारा 3 ए (4) में इस तरह के खंडन का प्रावधान है। इसलिए, हमारी राय में धारा 3 ए (2) केवल साक्ष्य के नियम (अनुमान) का प्रतीक है, लेकिन एक कानूनी कल्पना का निर्माण नहीं करती है। ड्राफ्ट्समैन द्वारा नियोजित भाषा इस निष्कर्ष पर गुमराह करने की संभावना है कि एक कल्पना बनाई गई है।- लेकिन पूरी धारा 3 ए के सही और उचित निर्माण पर एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह है कि धारा 3 ए ( ) में केवल ए शामिल है। अनुमान (साक्ष्य का नियम)।

39. 1997 के नियमों की योजना के तहत, पहले चार नियमों ने उपरोक्त तीन

प्रक्रियाओं में से तीसरी (पैरा 36 में उल्लिखित) को जोड़कर, उस वर्ग के निर्माताओं के ए. सी. पी. को निर्धारित करने की प्रक्रिया निर्धारित की, जिससे अपीलकर्ता संबंधित हैं। विधायक इस तथ्य से अवगत थे कि एक कारखाने में निर्मित की जा सकने वाली वस्तुओं की वास्तविक मात्रा केवल कारखाने के एसीपी पर निर्भर नहीं करती है। यह कई अन्य परिवर्तनशील कारकों पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, हालांकि एक निर्माता द्वारा नियोजित मशीनरी में माल की एक निश्चित मात्रा (अधिकतम प्रीडक्शन) का उत्पादन करने की तकनीकी क्षमता होती है, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल में निर्माता हमेशा अधिकतम उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि कारखाने को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या वित्त या कच्चे माल आदि की अनुपलब्धता होती है। 1997 के नियम के पहले चार नियम साक्ष्य की एक योजना बनाते हैं जिसके द्वारा उत्पादन की एक निश्चित मात्रा की संभावना का अनुमान (निर्माताओं की मशीनरी के तकनीकी विनिर्देश के आधार पर) बनाया जाना है। हालांकि, कानून निर्माता ने कल्पना की कि कुछ मामलों में ऐसी प्रक्रिया से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि एक निर्माता का एसीपी वास्तविक उत्पादन से कम है जो पहले के समय में एक ही मशीनरी को नियोजित करके प्राप्त किया गया था-एक निष्कर्ष जो स्थापित तथ्यात्मक डेटा के साथ असंगत है। इसलिए, नियम 5 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में कारखाने के एसीपी को 1997 के नियमों के लागू होने से पहले वित्तीय वर्ष में प्राप्त वास्तविक उत्पादन के बराबर माना जाना चाहिए। नियम 5 नियम 3 में निहित सूत्र को लागू करके एसीपी तक पहुंचने में त्रुटि की संभावना को पहचानता है। क्योंकि सूत्र स्वयं कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए, नियम 5 में प्रावधान है कि नियम 3 में निहित प्रक्रिया के अनुसार किए गए ए. सी. पी. का निर्धारण कुछ मामलों में उसमें इंगित परिस्थितियों में सुधार के लिए उत्तरदायी है।

40. लेकिन धारा 3 ए (4) का लाभ नियम 96 जेडपी (3) के तहत आने वाले निर्माताओं के एक उप-वर्ग को वार्षिक उत्पादन के संबंध में धारणा का खंडन करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 जेडपी की योजना के तहत आने वाले एक बड़े वर्ग का भी हिस्सा हैं।

41. लेकिन नियम 96 जेडपी के उप-नियम (3) की घोषणा के लिए, एक निर्धारिती जिसका एसीपी 1997 के नियमों के नियम 3 के अनुसार निर्धारित किया जाता है, अधिनियम की धारा 3 ए की उप-धारा (4) के तहत अपने वास्तविक उत्पादन और उस में कर देयता के निर्धारण की मांग करने का हकदार होगा।

42. ए. सी. पी. का निर्धारण एक बार का मामला है। नियम 3 में बताए गए कारकों से यह प्रतीत होता है कि एसीपी तब तक अपरिवर्तित रहेगा जब तक कि नियोजित मशीनरी में कोई बदलाव नहीं होता है और मशीनरी के 'उपयोग किए गए घंटों की संख्या' स्थिर रहती है। लेकिन "उपयोग किए गए घंटों की संख्या" समय-समय में विभिन्न कारकों के आधार में भिन्न हो सकती है, जैसे कि बिजली की उपलब्धता, पूंजी या श्रम आदि। इस तरह के बदलावों के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि किसी भी समय अंतराल के लिए कारखाने का वास्तविक उत्पादन एसीपी से कम हो। इसलिए, धारा 3 ए (4) के तहत यह घोषित किया जाता है कि एक निर्धारिती अपने कारखाने के वास्तविक उत्पादन के निर्धारण की मांग करने का हकदार है यदि यह एसीपी से कम है।

43. हमारी राय में, धारा 3 ए (4) के तहत प्रदान की गई ऐसी संभावना निर्धारिती के लिए समय-समय पर उपलब्ध एक आवर्ती अवसर है। हम इस निष्कर्ष पर उप-धारा (4) की भाषा को ध्यान में रखते हुए पहुंचते हैं, विशेष रूप से "केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त धारा 3 के तहत निर्दिष्ट दर पर ऐसे वास्तविक उत्पादन के संदर्भ में

निर्धारिती द्वारा देय शुल्क की राशि का निर्धारण करेगा"।

जाहिर है, निर्धारिती द्वारा देय शुल्क की राशि का निर्धारण एक बार का मामला नहीं है। इस तरह है निर्णय समय-समय पर किया जाना चाहिए। इसलिए, मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक अवधि के लिए वास्तविक उत्पादन की स्थापना के लिए साक्ष्य रखने का अवसर समय-समय पर निर्धारिती के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

44. 1944 के नियमों के नियम 96 जेडपी (3) द्वारा इस तरह के वैधानिक अधिकार को किसी भी तरह में कम किया गया है या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। नियम 96 जेडपी (3) उन कर निर्धारकों के लिए शुल्क के मूल्यांकन के संदर्भ में प्रासंगिक है जो मासिक आधार पर उत्पाद शुल्क के भुगतान का विकल्प चुनते हैं। ऐसे निर्धारिती द्वारा देय शुल्क मीट्रिक टन में  $\text{रु.}300 \times \text{ACP}$  होगा। नियम 96 जेडपी (3) में कहा गया है कि नियम 96 जेडपी (3) के तहत योजना (शुल्क की रियायती दर) का लाभ उठाने के इच्छुक निर्धारिती को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना आवश्यक है। टाई नियम उस समय के बारे में मौन है जब इस तरह के आवेदन की आवश्यकता होती है। लेकिन उप-नियम (3) उस समय को निर्धारित करता है जिसके भीतर शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक है, अर्थात्, "प्रत्येक महीने की शुरुआत में" और "प्रत्येक महीने की शुरुआत में नवीनतम"।

45. क्या एक निर्धारिती जो नियम 96 जेडपी (3) के संदर्भ में शुल्क का भुगतान करने के लिए एक बार चुनता है, उसे वास्तविक उत्पादन की परवाह किए बिना आने वाले सभी समय के लिए उक्त नियम के अनुसार गणना किए गए शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी जाँच की आवश्यकता है।



46. यह संभव है कि किसी दिए गए मामले में कोई निर्धारिती किसी दिए गए समय पर उप-नियम (3) के संदर्भ में गणना किए गए मासिक आधार पर शुल्क का भुगतान करने का विकल्प चुनता है, लेकिन कुछ महीने बाद (उस मामले के लिए एक महीने बाद भी), विभिन्न वैध कारणों से, उत्पादन (निर्धारिती कारखाने के) एसीपी से काफी नीचे विफल हो सकता है। यह संभव है कि कुछ मामलों में निर्धारिती के नियंत्रण से बाहर के कारणों से विनिर्माण गतिविधि पूरी तरह से बंद हो सकती है। यदि नियम 96 जेडपी (3) के तहत किसी निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प अनंत काल के लिए अच्छा माना जाता है, तो यह न केवल अतार्किक परिणाम देगा, बल्कि करों के असंवैधानिक संग्रह के लिए भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो निर्धारिती को नियम 96 जेडपी (3) की योजना से बाहर निकलने से रोकता है।

47. अग्रिम शुल्क का भुगतान करके एक महीने के लिए योजना का लाभ उठाने के बाद, यदि निर्धारिती अपने एसीपी के बराबर माल का उत्पादन करने में समर्थ नहीं है, तो हम ऐसा कोई कारण नहीं देखते हैं जो निर्धारिती को उत्पादन की उस मात्रा पर शुल्क की रियायती दर (अगले महीने के लिए) का लाभ उठाना जारी रखने के लिए मजबूर करता है जिसे वह प्राप्त करने में असमर्थ है। हमारी राय में निर्धारिती के पास नियम 96 जेडपी (1) के अनुसार उच्च दर पर लेकिन वास्तविक उत्पादन पर शुल्क का भुगतान करने का विकल्प होना चाहिए। उन निर्धारिती के लिए जिन्होंने उप-नियम (1) के अनुसार उच्च दर में शुल्क का भुगतान करने का विकल्प चुना, धारा 3 ए (4) का लाभ उपलब्ध है। नियम इसे प्रतिबंधित नहीं करता है, हालांकि प्रश्न यह है कि निर्धारिती इस तरह के विकल्प का उपयोग करने का कितनी बार हकदार है; चाहे वह वार्षिक हो या मासिक। एक ऐसा मामला है जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है।

48. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त बनाम वीनस कास्टिंग्स (पी)

लिड., (2000) 4 एस. सी. सी. 206, भारत संघ और अन्य बनाम सुप्रीम स्टील्स और जनरल मिल्स और अन्य, (2001) 9 एस. सी. सी. 645, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 जेड. पी. के उप-नियम (3) के अधिकारों के बारे में प्रश्न में इस अदालत के दो फैसलों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है। प्रतिवादी द्वारा यह भी निवेदन जाता है कि यह अदालत पहले ही घोषणा कर चुका है कि निर्धारिती जो उप-नियम (3) के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए एक बार विकल्प चुनता है, वह अपनी पसंद पर वापस नहीं जा सकता है।' भारत संघ और अन्य बनाम सुप्रीम स्टील्स और जनरल मिल्स और अन्य, (2001) 9 एस. सी. सी. 645,

“पैरा 3. निर्माता पहले एक वित्तीय वर्ष के दौरान दो बार विकल्प नहीं चुन सकता है।

नियम 96 जेड ओ के उप-नियम 3 के अनुसार भुगतान करने का विकल्प चुनना और फिर अधिनियम की धारा 3 ए (4) के तहत वास्तविक उत्पादन आधार में स्विच करना, यदि यह नियम 96 जेड ओ के उप-नियम 3 के तहत देय शुल्क से कम है। उक्त उप-नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके तहत विकल्प इस शर्त के अधीन उपलब्ध है कि एक बार इसे चुनने के बाद, उप-नियमों के तहत यदि कोई हो तो लाभ प्राप्त करें। (4) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 ए उपलब्ध नहीं होगी।.....”

49. उपर्युक्त दोनों मामलों में, यह अदालत केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 जेड ओ (3) पर विचार कर रहा था। न तो नियम 96 जेडपी (3) के अधिकार और न ही इसकी व्याख्या वास्तव में उपरोक्त में से किसी भी मामले में इस अदालत के

विचार के लिए आती है। हालांकि, वीनस कास्टिंग्स में पैरा 9 में नियम 96 जेडपी का एक संदर्भ दिया गया था और इस अदालत ने कहा कि "नियम 96 जेडओ और 96 जेडपी क्रमशः सिल्लों और बिलेट और गर्म फिर से घूमने वाले उत्पादों के निर्माता द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं, इन प्रावधानों के तहत परिकल्पित योजना समान है"।

50. विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, हमें इस निष्कर्ष को प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल लगता है कि दोनों नियमों की योजना समान है। नियमों के बीच व्यापक समानताएं हैं लेकिन वे समान नहीं हैं और हम बाद में अंतर को इंगित करेंगे और उनसे निपटेंगे।

51. वीनस कास्टिंग्स में, इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त दोनों नियमों में "निर्धारिती के विकल्प पर अपनाई जाने वाली दो वैकल्पिक प्रक्रियाओं" की योजना है और निष्कर्ष निकाला कि "निर्माता, यदि उन्होंने अपने विकल्प पर नियम 96 जेड ओ 0 (3) के तहत प्रक्रिया का लाभ उठाया है, तो अधिनियम की धारा 3A (4) के तहत उत्पादन क्षमता के निर्धारण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसे विशेष रूप से बाहर रखा गया है।"

"11. .... यह देखा जा सकता है कि इस धारा के तहत शुल्क स्पष्ट रूप से माल के उत्पादन पर है, लेकिन कर का माप माल के वास्तविक उत्पादन या किसी अन्य आधार पर निर्भर करता है। इसलिए कर का प्रभाव माल के उत्पादन पर पड़ता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि वार्षिक भट्टी क्षमता के आधार पर कर का संग्रह माल के उत्पादन से संबंधित नहीं है और यह अधिनियम के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। यह अभिनिर्धारित करने में कि क्या कोई सुसंगत

नियम अधिकार अधिकारातीत है, प्रस्तावना से लेकर अंतिम प्रावधान तक समग्र रूप से अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। यदि संपूर्ण अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ा जाता है तो यह उद्देश्य इंगित करता है और उस उद्देश्य को नियमों द्वारा पूरा किया जाता है, तो इसे अधिनियम के प्रावधानों के अधिकार अधिकारातीत नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्माता, यदि उन्होंने अपने विकल्प पर नियम 96 जेडओ (3) के तहत प्रक्रिया का लाभ उठाया है, तो अधिनियम की धारा 3 ए (4) के तहत उत्पादन क्षमता के निर्धारण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसे विशेष रूप से बाहर रखा गया है।”

उपरोक्त से दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस अदालत ने निर्णय के पहले के पैराग्राफ में नियम 96 जेडपी का संदर्भ दिया था, लेकिन जब यह निष्कर्ष पर पहुंचा, तो उसने केवल नियम 96 जेडओ (3) के बारे में बात की, लेकिन नियम 96 जेडपी (3) के बारे में नहीं। दूसरा, अधिनियम की धारा 3 ए (4) से संबंधित नहीं है। कारखाने की उत्पादन क्षमता के निर्धारण के साथ। यह केवल निर्धारिती के यह स्थापित करने के अधिकार से संबंधित है कि ए. सी. पी. के निर्धारण के बावजूद, प्राप्त वास्तविक उत्पादन निर्धारित ए. सी. पी. से कम है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि "यदि पूरे अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ा जाता है तो यह उद्देश्य इंगित करता है और उस उद्देश्य को नियमों द्वारा पूरा किया जाता है, तो इसे अधिनियम के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र में नहीं कहा जा सकता है।”

52. सम्मान के साथ, हमारी राय है कि कानून के इस तरह के कथन का पूर्ववर्ती या कानूनों की व्याख्या के किसी भी तय किए गए सिद्धांतों में कोई आधार नहीं

है। दूसरी ओर, यह अधिकारियों की एक लंबी सुलझी हुई पंक्ति के साथ संघर्ष में है कि अधीनस्थ कानून जो मूल अधिनियम के साथ संघर्ष में है, अस्थिर है:

“हुकुम चंद आदि। भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर. 1972 8 सी 2427:(1972) 2 एससीसी 601,

पैरा 8., अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि संप्रभु विधानमंडल के विपरीत, जिसके पास पूर्वव्यापी संचालन के साथ कानून बनाने की शक्ति है, अधीनस्थ कानून बनाने की शक्ति के साथ निहित प्राधिकरण को अपनी शक्ति की सीमाओं के भीतर कार्य करना पड़ता है और इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। अधीनस्थ अभिनिर्धारण और अधिनियमों के बीच प्रारंभिक अंतर इस तथ्य में निहित है कि एक अधीनस्थ अधिनियम बनाने वाला निकाय अपने प्रत्यायोजित या व्युत्पन्न प्राधिकरण की शर्तों से बंधा होता है और वह अधिनियम का न्यायालय, एक सामान्य नियम के रूप में इस प्रकार बनाए गए नियमों को तब तक प्रभावी नहीं करेगा, जब तक कि यह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि नियमों की वैधता के लिए पूर्ववर्ती सभी शर्तों को पूरा कर लिया गया है (देखें अधिनियम पर संदेह, पृष्ठ 297, छठा संस्करण)।

यह भी देखें: गोड्डे वेंकटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 828, पैरा 10 "

53. सुप्रीम स्टील्स में निर्णय तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था। नियम 96 जेड ओ के अधिकार सीधे-सीधे जारी किए गए थे-सुप्रीम स्टील "केंद्रीय

उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 96 जेड ओ के अधिकार को भी इस आधार में चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है-पैरा 1". वीनस कास्टिंग्स में इस अदालत ने उल्लेख किया (पैरा 7 में) कि "इन कार्यवाहियों में नियमों के प्रावधानों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि केवल उनकी व्याख्या और अनुप्रयोग की जांच की जानी चाहिए", हालांकि, विद्वान न्यायाधीश सुप्रीम स्टील्स ने राय दी कि विवाद को अंततः वीनस कास्टिंग्स में इस अदालत के फैसले से सुलझा लिया गया था।

54. उपर्युक्त दो निर्णयों में हमारे द्वारा देखी गई विभिन्न समस्याओं के अलावा, नियम 96 जेड पी (3) के तहत नियोजित भाषा में स्पष्ट अंतर हैं और यह योजना नियम 96 जेड ओ (3) की योजना के तहत अपनाई गई भाषा से अलग प्रतीत होती है।

55. नियम 96 जेड ओ शुल्क, मूल्यांकन और उत्पाद शुल्क के संग्रह से संबंधित है। गैर-मिश्र धातु इस्पात सिल्लियों और बिलेट के निर्माण पर शुल्क। ऐसी वस्तुओं पर शुल्क रु.750-प्रति मीट्रिक टन की दर से देय है। उप-नियम (3) उन निर्माताओं के मामलों में प्रति माह 5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि का शुल्क और संग्रह निर्धारित करता है जिनकी कुल भट्टी क्षमता तीन मीट्रिक टन है। हालांकि, ऐसी योजना निर्धारिती के विकल्प पर उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में एक निर्माता के पास निर्माता के वास्तविक उत्पादन के रु.750-प्रति मीट्रिक टन की दर से शुल्क का भुगतान करने के बजाय, उस महीने के लिए अपने वास्तविक उत्पादन की परवाह किए बिना, 5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान करने का विकल्प होता है। उक्त उप-नियम में तीन मीट्रिक टन की क्षमता कारखाने की क्षमता प्रति दिन या प्रति माह या प्रति वर्ष है या नहीं, यह नियम की भाषा से बहुत स्पष्ट नहीं है। इस अभिव्यक्ति को नियमों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है।

56. नियम 96 जेडपी (3) पर आते हुए, यह नियम के तहत आने वाले निर्धारिती को रु.300 प्रति मीट्रिक टन की रियायती दर पर शुल्क का भुगतान करने का विकल्प भी प्रदान करता है, जो उन निर्धारिती के दायित्व के विपरीत है जो प्रति मीट्रिक टन रु.400 का भुगतान करने के लिए उप-नियम (3) के तहत प्रक्रिया का लाभ उठाने का विकल्प नहीं चुनते हैं।लेकिन निर्धारिती के दोनों वर्गों को कारखाने के एसीपी पर गणना किए गए कुल शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।जबकि जो लोग उप-नियम (3) के तहत कर की कम दर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, वे हर महीने कर का भुगतान करते हैं और जो लोग उप-नियम (3) के तहत योजना का लाभ उठाने का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें उप-नियम (1) और (2) के तहत बताए गए शुल्क के वास्तव में देय होने के लंबे समय बाद कर का भुगतान करना पड़ता है।

57, नियम 96 जेड ओ (3) और 96 जेड पी (3) के बीच एकमात्र समानता यह है कि दोनों नियम उन निर्धारिती के मामलों में अधिनियम की धारा 3A (4) के तहत प्रक्रिया के लाभ को समाप्त करने का प्रयास करते हैं जो उप-नियम (3) के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने का विकल्प चुनते हैं जो नियम 96 जेड ओ और 96 जेड पी के तहत प्रदान किए गए शुल्क और संग्रह के सामान्य नियमों के अपवाद हैं।

58. इसलिए, हमें प्रतिवादी की इस दलील को प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल लगता है कि यह मुद्दा वीनस कास्टिंग्स और सुप्रीम स्टील्स में इस अदालत के निर्णयों में शामिल है।हमारी राय में, ऊपर वर्णित कारणों के लिए, इन दोनों निर्णयों को आगे की जांच की आवश्यकता है।इसके अलावा, ये निर्णय नियम 96 जेडपी (3) के अधिकारों से संबंधित नहीं थे।तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुप्रीम स्टील्स तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है, हम यह उचित समझते हैं कि

कानून के प्रश्न का निपटारा उचित संख्या वाली पीठ द्वारा किया जाए।इसलिए हम पंजीकरण को निर्देश देते हैं कि वह इस मामले को आगे के आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की समक्ष रखे।

देविका गुजराल

मामला बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया।



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।